almost 80 per cent. So, I would like to believe that the global financial crisis that has caused such a problem for Indian exports has reduced to an extent. In the meantime, of course, it is our constant endeavour to explore new markets and also to develop new markets for our products, be it Africa or be it Europe or be it America. This is a constant on-going process and the results are there before us to see. Regarding negative growth, Sir, I can assure the hon. Member that except for very few areas where we are having some problems, by and large most of the areas are, exclduing software, are beginning to show a positive export growth rate this year.

*103. *[The questioner (Shri Barjinder Singh Hamdard and Shri Kapil Sibal) were absent for answer vide page 33 infra].*

Schemes for Welfare of Primitive Tribes

*104. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of TRIBAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have sponsored some schemes for the uplift and welfare of primitive tribes;

(b) if so, the States where various primitive tribes are living;

(c) the schemes sponsored by Government for the welfare of these tribes;

(d) whether any such scheme has been sponsored by the Central Government for the welfare of Bonda tribes who are living in Malkangiri and Jeypore hills in Orissa; and

(e) if so, the details thereof alongwith the steps taken for the uplift of these tribes during the last three years?

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS (SHRI JUAL ORAM): (a) Yes, Sir.

(b) A Statement is laid on the table of House, *(see* below)

(c) Besides various Central and Centrally sponsored schemes for the development of Scheduled Tribes which are also available to Primitive Tribal Groups, a specific Central Sector scheme for the Development of Primitive Tribal Groups has been launched from the year 1998-99.

(d) The Central Sector scheme of development of Primitive* Tribal Groups is also available for Bonda Tribe.

(e) No proposal under the above scheme has been received from the State Government.

Statement

List of Approved Primitive Tribal Groups

1.	Andhra Pradesh	1. Bodo Gadaba
		2. Bondo Poraja
		3. Chenchu
		4. Dongaria Khonds
		5. Gutob Gadaba
		6. Khond Poroja
		7. Kolam
		8. Kondareddis
		9. Konda Savaras
		10. Kuttiya Kondhs
		11. Parangiperja
		12. Thoti
2.	Bihar	13. Asur
		14. Birhor
		15. Birjia
		16. Hill Kharia
		17. Korwa
		18. Mai Pharia
		19. Paharias
		20. Sauria Pahariya
3.	Gujarat	21. Savar
		22. Kathodi
		23. Kotwalia
		24. Padhar
		25. Siddi
4.	Karnataka	26. Kolgha
		27. Jenu Kuruba
5.	Kerala	28 Koraga
		29 Cholanaikayan (A sction of Kattunay-akan)

6. Madhya Pradesh	30. Kadar 31. Kattunayakan 32. Kurumbas 33. Koraga 34. Abujh Maria 35. Baiga 36. Bhaira 37. Hill Korwa 38. Kamar 39. Sahariya
7, Maharashtra	40. Birfeot 41. Katkaria (Kathodi) 42. Kolam
8. Manipur 9	43. Maria Gond 44. Maram Naga
Orissa	45. Birhor 46. Bondo 47. Didayi 48. Dongria-Khond 49. Juang 50. Kharia 51. Kutia Khond 52. Lanjia Saura 53. Lodha 54. Mankirdia 55. Paudi Bhuyan 56. Saura
10. Rajasthan	57. Chuktia Bhunjia
11. Tamil Nadu	58. Seharias 59. Kattu Naickans 60. Kotas 61. Kurumbas 62. Irulas 63. Paniyans
12. Tripura	64. Todas 65. Reangs

13.	Uttar Pradesh	66. Buxas 67. Rajis
14.	West Bengal	68. Birhor 69. Lodhas 70. Totos
15.	Andaman & Nicobar Islands	71. Great Andamanese 72. Jarawas 73. Onges 74. Sentenelese 75. Shompens

श्री भगवान माझी: सभापति महोदय, स्कीमस फॉर वेलफेय आफ प्रिमिटिव ट्राइब्स के बारे में मैने जो क्वेश्चन पूछा था, मंत्री महोदय ने उसमें 75 ट्राईब्स को प्रिमिटिव ट्राइब्स का नाम दे दिया है, लेकिन जहां तक मैने देखा है वे ट्राइब्लस आज भी बिलो पावर्टी लाइन है । अभी तक जितनी भी सैंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स उनको अपलिस्ट करने के लिए चलाई जा रही है। उनमें भी वे आगे नहीं बढ़ पा रहे है, वे पीछे है :

तो मैं मंत्री महोदय से और सरकार से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उनको ऊपर उठाने के लिए कुछ नई स्कीम्स बनाने के बारे में सोच रही हैं ?

श्री जुएल उराम : सर, अभी तक सरकार ने नई स्कीम सोची नहीं है , लेकिन ये जो 75 प्रिमिटिच ट्राइब्स ग्रुप्स है उनका ऐजुकेशनली , इकनॉमिकली एवम सोशियली उत्थान हो, इसके लिए केन्द्रीय सरकार की तरफ से स्कीम्स चालू है । केस-टू-केस बेसिस पर बीच-बीच में उनको रिव्यू करके इन ट्राइब्स ग्रुप के लिए जो-जो काम करने चाहिए, उस बारे में सरकार की तरफ से काम चालू है ।

श्री भगवान माझी: मान्यवर, उडीसा का सबसे बेकवर्ड डिस्ट्रिक्ट कोरापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां बोंडा हिल है और वहां बोंडा ट्राइब्स रहते है । अभी भी वहां औरतें 60 परसैंट कपड़ा नहीं पहनती है नंगी रहती है । उनके लिए सरकार की ओर से बोंडा ट्राइबल डेवलमेंट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था, उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ । इसलिए मै मंत्री महो दय से जानना चाहता हूं कि क्या बोंडा ट्राइब्स के लिए और कुछ नई स्कीम चलाने की व्यवस्था है और अंडमान निकोबार में झरूआ ट्राइब्स है, वे लोग अभी भी , पुरूस और महिला सब, नंगे रहते है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए सरकार की ओर से क्या व्यवस्था की जाएगी, यह मैं सरकार से जानना चाहता हूं?

श्री जुएल उराम: सर, बोंडा ट्राइब के उत्थान के लिए बोंडा डेवलमेट एजेंसी, बी.डी.ए. कार्यक्रम लागू किया गया है । उसमें अभी तक सरकार की ओर से ईयर-वाईज, एक्स्पैंडिचर

1996-97 में 4,51,238, 1997-98 में 3,17,813 रूपए और 1998-97 में 5,59,223 रूपए रखा गया है। महोदय, 5,000 बोंडा ट्राइब्स है। उनके लिए स्पैशल स्कूल है, रेज़िडेंशियल स्कूल है जिसमेम उनकों पढाया जाता है।

सभापति महोदय, प्रिमिटिव ट्राइब्स की स्पैशल प्रोब्लम है उनका मोटिवेशन करना। उनका जो रहन-सहन है, उससे ऊपर आकर वे आधुनिक रहन-सहन अपनाएं, यह परिवर्तन लाने में टाइम लगता है। फिर भी ये 5,000 बोंडा ट्राइब्स हो है उनमें काफी इंप्रुवमेट हुआ है। अब उनमें आधे से अधिक लिग पढ़ना-लिखना जानते है, कपड़े पहनने में उनकी रूचि बढ़ी है। पहले वे दबा नहीं खाते थे, अब उनकी दबा खाने में रूचि बढी है।

जहां तक अंडमान- निकोबार की झरूआ ट्राइब , प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप का सवाल है हमारे पास जो इन्फोरमेशन है उसके मुताबिक उन लोगों के लिए प्लांटेशन प्रोग्राम चलाए गए है और हैल्थ प्रोग्राम्स में भी उनके लिए व्यवस्था की गई है। उनकी अवेयरनस बढ़ाने के लिए कि साफ-सफाई से कैसे रहे, नंगे न रहकर कपड़े कैसे पहनें, इसके लिए उनको मोटिवेट करने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है। इस साल स्पैशल असिस्टेंस से हैल्थ कैंप करके, उनको मोटिवेट करके उनके रहन-सहन में परिवर्तन लाने के लिए कोशिश की जाएगी, यह लक्ष्य रखा गया है।

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir, there are certain things to be done for the development of the primitive people. Even for motivation, they require the people among them, who are educated, who can understand their language, and who can converse with them in their own language. Unfortunately, in your own recruitment rules, even for the teachers in the primitive areas, you have fixed certain norms, certain educational qualifications and, as a result, you do not find people among theni. There should be some relaxation. Even under the P.D.S., the contractors are not taking foodgrains to those areas because you are not paying them the transportation charges. Foodgrains are given, but they are not being paid the transportation charges. They are asking the Government for transportation charges, but you are not paying them. As a result of this, some of these benefits are not reaching them at all. So, the existing rules are to be relaxed in certain cases and special efforts have to be made in conversing with them and in converting them. My point is, whether the Government has taken note of these things the primitive people themselves, who are educated, should be engaged in motivation work and with regard to the P.D.S., relaxation has to be given and

additional expenses are to be born by the Government to see that foodgrains, kerosene, etc., are reached to those areas.

श्री जुएल उराम: सर, प्रिमिटव ट्राइब्स को डेवलप करने के लिए माइक्रो प्रोजेक्ट एप्रोच है । उसके लिए उनकी एक सोसायटि रजिस्टर करके उन्ही के ग्रुप में से कुछ लोगों को इन्वॉल्व करके यह काम चालू किया जाता है । जहां तक अधिकारियों का सवाल है यह बात देखने में आई है कि वे शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए है। अभी हम लोगों ने इसकी स्टडि नहीं है । आगे चलकर स्टडि करके माननीय सदस्य हो सुझाव दे रहे है उनको मद्देनज़र रखते हुम हम इस काम को करेंगे ।

श्री संघ प्रिय गौतम: सभापति महोदय, मुझे एक संसदीय समिति के माध्यम से बोंडा पहाडियों में जाने का मौका मिला था । यह सही है कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार की ओर से वहां पर विद्यालय की स्थापना की गई और विकास केन्द्र भी स्थापित किया गया है पर मैंने यह देखा है कि वहां स्त्रियां ही नहीं बल्कि पुरूष भी नंगे ही रहते है और वे जरा सा कपड़ा ऐसा कि बैठकर अपने गुप्तांग़ा को छिपा सकें, पहनते है और बाकी कोई कपड़ा नहीं पहनते । अगर कोई अनजनबी वहां पर उनकी तरफ जाए तो उसे वे मारने के लिए दौड़ते है, यह एक अलग बात है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन्न करना चाहता हूं कि वहां पर जंगलात की प्राकृतिक देन है और वहां फल-फूल और सब्जियां काफी मात्रा में पैदा होती है । निकट के एक नगर मे बहगियों पर लादकर ये नेंगे बोंडा आदिवासी इन्हें बेचने के लिए जाते है । क्योंकि उनको उसका मूल्य न के बराबर दिया जाता है । तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई क्रय केन्द्र उनके द्वारा जगलों से इकट्ठा किए हुए पदार्थो के ले वहां पर स्थापित करेगी और उचित मूल्य मेम क्रय करके उनको उचित दाम मुहैया कराएगी ?

श्री जुएल उराम: सरकार, इसके लिए हमारे पास आलरेडी ट्राइफेड है, ट्राइबेल का जो प्रोडक्ट है, उसको परचेज़ करके उसकी मार्केटिंग करने के लिए । यह स्पेसिफिक प्रश्न जो माननीय सद्स्य ने उठाया है , मैं उसकी जांच कराऊंगा कि इसमें क्या हो रहा है और उसमें स्पेशल परचेज़ करने की व्यवस्था कराऊंगा ।

कुमारी फ्रिडा टोपनो: चेयरमैन सर, बोंडा हिल्स में एक बार मुझे भी जाने की मौका मिला था जब मै वहां सर्विस करती थी । वहां रेज़ीडेंशियल स्कूल भी खुला था जो एम. ई. स्टैडर्ड तक था । वहां एक अफसर थे जो उनके साथ बहुत दिनों तक रहे थे । उनकी भाषा भी वे सीख गए थे और घर-घर जाकर वे काम करते थे । उस समय वह स्कूल एम. ई. स्टैंडर्ड तक था तो मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या वह अफसर अभी है या नहीं क्योंकि वह वहां के लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते थे । दूसरे मैं यह जानना चाहती हूं कि वह स्कूल अब हाईस्कूल हो गया है या नहीं? और कितने स्टुडेंट्स उसमें से पास करके निकले हैं ?

श्री जुएल उराम: सर, यह इनफार्मेशन इमीडिएटली तो उपलब्ध नहीं है लेकिन बाद में मैं माननीय सदस्या को यह इनफोर्मेशन दे दूंगा।

FDI in tobacco sector

†*105. SHRI J. CHITHARANJAN:
SHRI GAYA SINGH:

Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are taking a fresh look on the question of allowing 100 percent FDI in tobacco sector;

(b) if so, the details thereof; and

(c) how many 100 percent FD Is have been allowed, so far, in the tobacco sector and which are they?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (DR. RAMAN): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

(a) to (c) The existing guidelines for consideration of Foregin Direct Investment (FDI) proposals by Foreign Investment Promotion Board (FIPB) do not stipulate any ceiling on the extent of foreign equity participation, *inter alia,* in sectors pertaining to consumer non durables, which include cigarettes. However, as there has been no precedent of 100% FDI approval in cigarettes so far, it was felt necessary to clarify the position *vide* Press Note No. 11 (1998 series) dated 27th August 1998, that proposals for manufacture of cigarettes with FDI up to 100% shall be considered by FIPB subject to the provisions relating to compulsory licensing under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951. This has been done with a view to lending greater transparency in decision making.

There has been no subsequent change in the guidelines relating to foreign investment in tobacco and cigarette industry.

---

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri J. Chitaranjan.